

उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता नयिम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखण्ड सरकार ने **समान नागरिक संहिता (UCC)** के नयिमों को मंजूरी दे दी है और **जनवरी 2025** के अंत तक कानून के लिये राजपत्र अधिसूचना जारी करने की योजना है, जिससे इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा।

मुख्य बटु

- **UCC के प्रमुख प्रावधान:**
 - फरवरी 2024 में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता (UCC) आदिवासी समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखती है।
 - यह हलाला, इद्दत और तलाक जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाता है, जो **मुस्लिम प्रसनल लॉ** के तहत प्रथाएँ हैं।
 - यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में **समान अधिकार प्राप्त हों**।
 - संहिता में **विवाह और तलाक के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है**, जिसका अनुपालन न करने पर सरकारी लाभों से वंचित होना पड़ेगा।
 - **अपंजीकृत लवि-इन संबंधों** के लिये कड़े प्रावधान मौजूद हैं, हालाँकि ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाता है।
- **कार्यान्वयन उपाय:**
 - सरकार ने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार अधिकार, लवि-इन रलेशनशिप और लवि-इन रलेशनशिप की समाप्त के पंजीकरण के लिये एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया है।
 - नागरिक अपने डेटा और आवेदन की स्थितिको मोबाइल फोन या घर से देख सकते हैं।
 - **सामान्य सेवा केंद्रों (CSC)** को ऑनलाइन पंजीकरण के लिये अधिकृत किया गया है।
 - इंटरनेट सुविधा से वंचित दूरदराज के क्षेत्रों में CSC एजेंट घर-घर जाकर पंजीकरण सेवाएँ प्रदान करेंगे।
 - सरलता और सुविधा के लिये ईमेल और एसएमएस के माध्यम से **आधार-आधारित पंजीकरण** और ट्रैकिंग की शुरुआत की गई है।
 - ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण तंत्र भी स्थापित किया गया है।



UNIFORM CIVIL CODE

All sections of the society irrespective of their religion shall be treated equally according to a National Civil Code - the Uniform Civil Code.

THEY COVER AREAS LIKE



Marriage



Divorce



Maintenance



Inheritance



Adoption



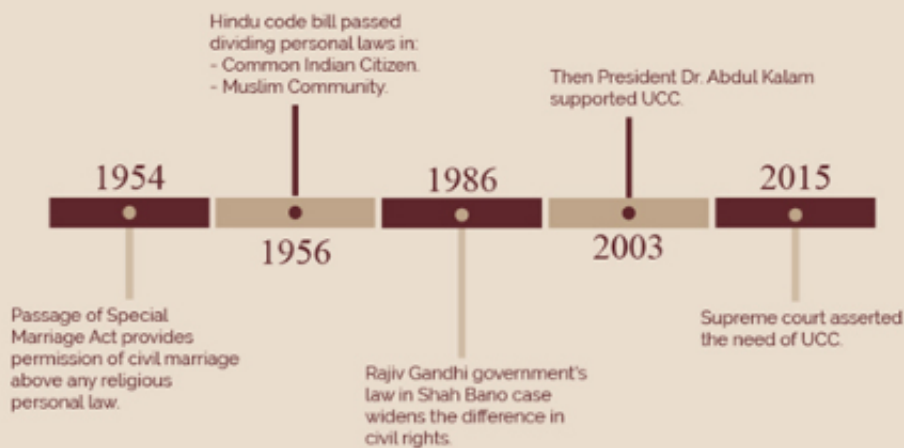
Succession of Property

It is based on the premise that there is necessarily no connection between religion and personal law in a civilized society.

"UCC refers to a common set of laws governing civil rights of every citizen."

Article 44 of Directive Principles sets duty of state for implementing UCC.

TIMELINE



The dialogue for UCC was started by the Law Commission in the year 2016